भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
(21–22–23 सितम्बर, 2007)
स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे सभागार
पं0 दीनदयाल परिसर (भोपाल)

राजनीतिक प्रस्ताव

राष्ट्र आज राजनैतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। संप्रग के घटक दलों के बीच संबंधों में दरार आने तथा केंद्रीय सरकार को अल्पमत में बदलने की वामपंथी–धमकी से मध्यावधि चुनाव की संभावनाएं अवश्यंभावी दिखती है। नीतिगत निर्णयों पर संप्रग व उसके घटक दलों के मतभेद ने सरकार की निर्णय–प्रक्रिया को कुंद कर दिया है। संप्रग नेतृत्व की विश्वसनीयता खतरे में है। सहयोगी दलों के बीच आरोप–प्रत्यारोप, खींचतान और यहां तक मंत्रियों के बीच का युद्ध रोजमर्रा की बात है। संप्रग सरकार सत्तासीन तो है, लेकिन शासन नाम की कोई चीज दिखती नहीं। सरकार नेतृत्वहीन, दिशाहीन और महज कुछ दिनों के खातिर सत्ता से चिपकी हुई है। दरअसल, संप्रग–वाम गठबंधन के घटक दल संभावित चुनाव को देखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हैं।

आर्थिक संबंधी नीतिगत निर्णय सबसे बुरी तरह से प्रभावित हैं। राजग के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था ने जो गति पकड़ी, वह और तेज हुई होती, यदि नीतिगत निर्णय जारी रहे होते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का मुख्य मकसद सिर्फ कुर्सी बचाना था। सरकार मूल्य वृद्धि एवं सामान्य उपभोक्ता एवं कृषि क्षेत्र प्रबंधन में पूर्णतः विफल रही है। किसानों की आत्महत्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।

चुनाव की अवश्यंभावी संभावनाओं को देखते हुए संप्रग सरकार का ध्यान सुशासन व नीतिगत मामलों पर नहीं है, बल्कि उसका पूरा जोर देश की सामाजिक समरसता को तार–तार कर वोट बैंक बनाने पर है। यह अपना हर निर्णय अल्पसंख्यक राजनीति को ध्यान में रखते हुए ले रही है, ताकि मुस्लिम मतदाताओं को राजनैतिक शक्ति के उपस्कर के रूप में इस्तेमाल हो सके। देश के पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं से धुसपैठ बढ़ी है। आतंकवाद का कहर यथावत जारी है और आतंकी हमले ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्यों व छद्म निरेपक्ष दलों के राज्यों में हो रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि राज्य के पुलिस प्रशासन को संकेत मिले हैं कि आतंकी ठिकानों की खोज, उसकी तहकीकात व खात्मे पर सुस्ती बरती जाय। आतंकियों से निपटने के लिए संप्रग सरकार ने जो रास्ता चुना है वह 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के राजमार्गों से नहीं, बल्कि वोट बैंक की तंग गलियों से गुजरता है, जिसका एकमात्र मकसद वोट बैंक की राजनीति को और मजबूत करना है। चिंताजनक बात यह है कि धुसपैठ बढ़ रहा है और भारत अब यह दावा नहीं कर सकता है कि वह अल–कायदा से मुक्त है। स्थानीय आबादी के कुछ वर्गों द्वारा आतंकवादियों को हर संभव सहायता (लॉजिस्टिक सपोर्ट) मिलती है। गोला–बारूद, हथियार और विस्फोट सामग्रियों से आतंकवादियों की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है और वे चुने गए ठिकानों पर अपनी इच्छानुसार हमले करने में सक्षम हैं। देश के पास कोई प्रभावकारी आतंक–निरोधी कानून नहीं है। अगर आतंक–निरोधी कानून होता तो खुफिया एजेंसियां, आतंकी गतिविधियों का पता लगाने तथा कठोर कानून के तहत आतंकियों को दोषी साबित करने में और सक्षम होतीं। पोटा को रद्द किए जाने के बाद संघीय सरकार ने ऐसे कानून पर अपनी सहमति रोक रखी है, जो राजस्थान व गुजरात जैसे राज्यों में संगठित अपराधों से निपटने में सक्षम होता। उल्लेखनीय है कि भाजपा शासित राज्यों में कठोर संकेतों के चलते आतंकी हमले बहुत कम हुए, क्योंकि आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस को अधिकार प्राप्त थे।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

आतंकी अपराधों से निपटने के लिए हमारी खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों की क्षमता में गंभीर ह्रास हुआ है।

राम–सेतु को नष्ट करने के प्रति केंद्रीय सरकार के दृष्टिकोण ने देशवासियों के विश्वास (संप्रग सरकार के इरादे के प्रति) को हिला दिया है। राम–सेतु आस्था का प्रतीक है। इसका संदर्भ इतिहास, पौराणिक कथाओं और धर्म में मिलता है। संप्रग और इसके सहयोगी राम सेतु को नष्ट करना चाहते हैं, जबकि इसका वैकल्पिक एलाइनमेंट संभव है। दरअसल, इनका असल उद्देश्य हिंदू मस्तिष्क पर चोट पहुंचाना है। अर्थशास्त्रियों ने इस प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। पर्यावरणविद् समुद्री वातावरण पर पड़ने वाले इसके कुप्रभावों से चिन्तित हैं। इसके बावजूद चैनेल बनाने के लिए संप्रग सरकार की राम–सेतु को नष्ट करने की जिद, अत्यंत निंदात्मक निर्णय है। संप्रग का दुस्साहस ही था कि देश के सर्वोच्च न्यायालय को इसने दलील दी कि राम और राम–सेतु दोनों पौराणिक कल्पना है, जिसकी आम जनता में घोर प्रतिक्रिया हुई। संप्रग सरकार के गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया हुई और इसकी राजनैतिक कीमत ने संप्रग को अस्थिर कर दिया है।

सच्चर आयोग की सिफारिशों को संप्रग सरकार ने मान लिया है। सच्चर कमेटी का चार्टर सामाजिक विघटन पैदा करता है। सच्चर कमेटी का सार यह है कि धर्म के आधार पर नौकरियों में आरक्षण हो व विकास की प्राथमिकता उन क्षेत्रों को प्राप्त हो, जिन पर एक धार्मिक समुदाय के लोग बसते हों तथा समुदाय आधारित बजटीय व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री की घोषणा कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यको खासतौर पर मुस्लिमों का पहला हक है, सरकार के इरादों को जाहिर कर देता है। भाजपा का स्पष्ट मत है कि सच्चर कमेटी की सिफारिशें गैर–संवैधानिक हैं। ये विघटनकारी (सामाजिक) हैं और इनका क्रियान्वयन संभव नहीं। यदि विकास सिर्फ उन क्षेत्रों का होता है, जिन पर एक खास समुदाय रहता है, तो बंटवारे से उपजी प्रतिक्रिया सच्चर कमेटी की सिफारिशों के क्रियान्वयन को असंभव बना देगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार से सच्चर समिति को पूरी तरह से निरस्त करने की मांग करती है तथा देश में गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को सभी क्षेत्रों में धार्मिक आधार से अलग कर पूरा करने की मांग करती है।

कश्मीर पर संप्रग सरकार की कोई गंभीर राजनैतिक विचार नहीं है। जबकि कश्मीर सीमापार आतंक से लगातार जूझ रहा है और संप्रग और इसके मित्र दल एक अस्वीकार्य प्रस्ताव के साथ आ चुके हैं, जिससे शेष भारत के साथ संवैधानिक बंधन और कमजोर होगा। धारा 370 एक अलग दर्जे (हैसियत) का प्रतीक है। 57 साल की यात्रा में धारा–370 ने अलग दर्जे से अलगाववाद की मनस्थिति पैदा की है। फिर भी संप्रग के मित्र ने केवल इसे जारी रखने की वकालत कर रहे हैं, बल्कि इससे एक कदम और आगे बढ़कर 1953 से पूर्व की स्थिति की बहाली, स्वायत्तता और स्वशासन की मांग कर रहे हैं। कश्मीर की समस्या सीमापार आतंकवाद, सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करने की है। राज्य विधान सभा या राज्य सरकार ने शक्ति की कमी की शिकायत कभी नहीं की। जम्मू–कश्मीर की असल समस्या को हल करने के बजाय संप्रग और इसके मित्र ऐसे समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, जो खुद समस्या से बड़े हैं। यदि उनकी नीतियों को स्वीकार कर लिया जाय तो पृथक दर्जे से अलगाववाद की यात्रा वास्तव में पूरी हो जाएगी।

बांग्लादेश से भारतीय क्षेत्र में अवैध घुसपैठ लगातार जारी है। पिछले दो सालों में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को 'आईएमडीटी एक्ट' और 'फॉरेनर्स कंट्रोल ऑर्डर' पर फटकार लगाई है। दरअसल, संप्रग ने घुसपैठ को प्रोत्साहित किया है और इसे वे संभावित वोट के रूप में देखते हैं। बांग्लादेश में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। वे अवैध घुसपैठियों के साथ मिलकर एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हाल ही में हुए हैदराबाद बम विस्फोट में हुजी का हाथ अब स्पष्ट हो चुका है, जो बांग्लादेश से संचालित अल–कायदा का एक फ्रंट है। घुसपैठ के कारण देश की जनसंख्या समीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पूरे देश में व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी का यह विचार है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का पुनरीक्षण करते हुए विदेशियों की पहचान अबिलम्ब की जाय। यह आवश्यक है कि बाड़ लगाने की कार्यवाई त्वरित रूप से की जाय। भाजपा का यह मानना है कि आईएस.आई हिन्दी भाषियों के हत्याओं में उनका पूरा हाथ है।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

संप्रग सरकार के राजनीतिक समर्थकों द्वारा प्रमुख खुफिया एजेंसी– सीबीआई– के दुरूपयोग से संप्रग सरकार ने भष्ट्राचार को संस्थागत रूप दे दिया है। ऐसा तंत्र विकसित किया गया, जिसमें विधि मंत्रालय की कानूनी सलाह सीबीआई के लिए बाध्यकारी हो, ताकि जांच–पड़ताल और अभियोग को प्रभावित किया जा सके। ऐसे कुछ ताजा उदाहरण– ओट्टोवियो क्वात्रोची, अजित योगी, सिबू सोरेन और लालू प्रसाद यादव के मामले हैं। यह कुछ और नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संस्थागत उल्लंघन है।

भारत–अमेरिकी परमाणु समझौते को पूरा करने के लिए सरकार ने जो दृढ़ संकल्प दिखाया है वह वाकई आश्चर्यजनक है, जबकि इसके कुछ हिस्से भारत के हितों के विपरीत हैं। संसदीय बहुमत इसके खिलाफ है। भाजपा इसका विरोध इस आधार पर करती है कि यह भारत के परमाणुविक विकल्प को सीमित करता है। परमाणु समझौते पर सरकार ने जिस ढंग से संसद के बहुमत–विचारों की अनदेखी की है, उससे साफ हो जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संप्रग सरकार ज्यादा गंभीर नहीं है।

परमाणु समझौते का नतीजा यह है कि कांग्रेस पार्टी व वामदलों के बीच खुला संघर्ष छिड़ चुका है। वामपंथियों का पाखंड इस तथ्य से स्पष्ट हैं कि वे आलोचना का ढिंढोरा तो पिटते हैं, लेकिन वे कार्यवाही करने में अब भी अनिच्छुक हैं। जो भी हो, यह स्पष्ट हो चुका है कि संप्रग और वामपंथियों के बीच की खाई अब पाटी नहीं जा सकती।

संप्रग सामूहिक रूप से गैर–जिम्मेदार कैबिनेट की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री के अधिकार को शायद ही कभी सम्मान मिलता है। मंत्रियों के बीच की आपसी–खींचतान रोजमर्रे की बात है। राम–सेतु मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल एएसआई का विवादित हलफनामा के पश्चात एक–दूसरे के खिलाफ मंत्रियों के बयान से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस दरबार में एक गृह–युद्ध जारी है। सरकार में किसी का शासन नहीं है। पिछले साढ़े तीन वर्षों में राष्ट्रीय झुकाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश एक वैकल्पिक सरकार की तरफ देख रहा है। संप्रग सरकार की गिरना अब राष्ट्रीय आकांक्षा बन गई है। प्रथमतः देश को एक मजबूत और सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता है, दूसरा– प्रभावी प्रशासन तथा तीसरा– राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गंभीर चिंता करने की जरूरत है। संप्रग सरकार की इन गंभीर मुद्दों के प्रति असफलता अब राष्ट्रीय आकांक्षा रूप में प्रकट हो चुका है। देश फिर से भाजपा की ओर देख रहा है, ताकि वह राजग का नेतृत्व कर इन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके।

भाजपा अपने कार्यकत्ताओं का आह्वाहन करती है कि संप्रग के कुप्रशासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करे तथा देश के हर कोने में जाकर भाजपा को तैयार रखे, ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को स्वीकार कर सके।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com